भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3954
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

बहुद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समितियां

†3954. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बहुद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समितियां की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी प्राथमिक कृषि समितियों की स्थापना की गई है और पीएसी के अंतर्गत राज्यवार क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है । इस योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), इत्यादि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा के अभिसरण द्वारा पांच वर्षों की अवधि के दौरान देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (M-PACS), डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करना है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् (दिनांक 27.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार) देश में कुल 12,957 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं । इसका राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है ।

पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों के विविधीकरण हेतु सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर परिचालित कर दी है जो उन्हें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों का प्रापण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, कॉमन सेवा केंद्रों (CSCs), उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्यकलाप, आदि जैसे 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाती हैं । अब तक, 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने आदर्श उपविधियां अपना ली हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श उपविधियों के साथ संरेखित हैं ।

अब तक 42,080 पैक्स कॉमन सेवा केंद्रों (CSCs) के रूप में; 36,193 पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में और 22,311 पैक्स उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में कार्य कर रहे हैं । इनका राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक-I

नवपंजीकृत सहकारी समितियां				
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**पैक्स**	**डेयरी**	**मात्स्यिकी**	**कुल (PACS/DCS/FCS)**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	7	9
आंध्र प्रदेश	0	896	1	897
अरुणाचल प्रदेश	12	9	12	33
असम	59	233	29	321
बिहार	25	283	0	308
छत्तीसगढ़	0	136	195	331
गोवा	12	0	0	12
गुजरात	291	435	7	733
हरियाणा	2	43	5	50
हिमाचल प्रदेश	57	350	4	411
जम्मू और कश्मीर	84	1005	29	1118
झारखंड	44	131	73	248
कर्नाटक	128	453	17	598
लद्दाख	0	3	1	4
लक्षद्वीप	0	0	7	7
मध्य प्रदेश	16	443	154	613
महाराष्ट्र	148	668	73	889
मणिपुर	68	17	10	95
मेघालय	193	12	1	206
मिजोरम	25	2	2	29
नागालैंड	12	0	2	14
ओडिशा	1535	0	0	1535
पुड्डुचेरी	2	2	3	7
पंजाब	0	80	0	80
राजस्थान	760	1232	3	1995
सिक्किम	23	34	0	57
तमिलनाडु	21	478	21	520
तेलंगाना	0	15	67	82
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	0	1	5
त्रिपुरा	38	0	2	40
उत्तर प्रदेश	94	1181	189	1464
उत्तराखंड	0	66	81	147
पश्चिम बंगाल	13	86	0	99
कुल	**3,667**	**8,294**	**996**	**12,957**

*****

अनुलग्नक-II

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), कॉमन सेवा केंद्र (CSC) और उचित मूल्य की दुकान (FPS) के रूप में कार्य कर रहे पैक्स का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	PMKSKs के रूप में पैक्स	CSCs के रूप में पैक्स	FPS के रूप में पैक्स
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	3	0
2	आंध्र प्रदेश	1246	1866	70
3	अरुणाचल प्रदेश	0	8	23
4	असम	0	620	402
5	बिहार	1483	3115	2774
6	छत्तीसगढ़	2058	1897	1180
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	8	7
8	गोवा	2	34	64
9	गुजरात	3328	1979	798
10	हरियाणा	743	241	35
11	हिमाचल प्रदेश	763	797	1948
12	जम्मू और कश्मीर	144	481	30
13	झारखंड	363	1217	581
14	कर्नाटक	1797	1273	2661
15	केरल	976	12	230
16	लद्दाख	0	7	0
17	मध्य प्रदेश	4517	3793	3833
18	महाराष्ट्र	842	6055	1559
19	मणिपुर	39	77	1
20	मेघालय	0	75	4
21	मिजोरम	0	14	0
22	नागालैंड	0	7	1
23	ओडिशा	1636	628	77
24	पुड्डुचेरी	6	27	1
25	पंजाब	1590	1770	103
26	राजस्थान	4030	5096	1366
27	सिक्किम	0	53	56
28	तमिलनाडु	3183	4453	3949
29	तेलंगाना	679	536	24
30	त्रिपुरा	7	155	84
31	उत्तर प्रदेश	6,295	5126	196
32	उत्तराखंड	466	625	23
33	पश्चिम बंगाल	0	32	231
	कुल	**36,193**	**42,080**	**22,311**

*****